भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 939
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सक्रिय दवा घटक

939. श्री अरुण गोविलः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को किफायती दवाइयों के बड़े पैमाने पर निर्माण और 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में जाना जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने विशेषकर एपीआई निर्यातकों द्वारा दबाव की रणनीति को देखते हुए दवाइयों के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल के रूप में प्रचलित सक्रिय दवा घटक (एपीआई) या बल्क ड्रग्स के घरेलू उत्पादन के लिए प्रयास किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में एपीआई निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन से विशेषकर एपीआई निर्यातकों द्वारा दबाव की रणनीति को देखते हुए आयात में कितनी कमी आई है; और
(घ) भारत के द्वारा एपीआई निर्माण में कब तक आत्मनिर्भर बनने की सम्भावना है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी, हाँ। भारत वहनीय दवाओं के बड़े स्तर पर विनिर्माण के लिए जाना जाता है और इसे विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। भारत का औषध उद्योग मात्रा के अनुसार औषध निर्यात के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के अनुसार 11वां सबसे बड़ा उद्योग है, जिसका वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल वार्षिक कारोबार ₹4,71,898 करोड़ है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹2,45,962 करोड़ मूल्य के औषध का निर्यात किया।

(ख) से (घ): जी, हाँ। सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, एपीआई के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन हेतु व्यापक प्रयास किए हैं, जिन्हें आमतौर पर बल्क औषधि के रूप में जाना जाता है और जो दवाइयों के विनिर्माण के लिए इनपुट का कार्य करते हैं, ताकि औषध उद्योग की आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर पूरा किया जा सके। इस उद्देश्य से, निम्नलिखित योजनाएँ शुरू की गई हैं:

(i) *भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम) / औषधि मध्यवर्ती (डीआई) / सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (जिसे बल्क औषधि हेतु पीएलआई योजना के रूप में भी जाना जाता है):* इस योजना, जिसका कुल बजटीय परिव्यय ₹6,940 करोड़ है, का उद्देश्य महत्वपूर्ण औषधियों, जिनका कोई विकल्प नहीं हैं, को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण सक्रिय औषधीय सामग्री (एपीआई) की

आपूर्ति में व्यवधान से बचना है, ताकि एकल स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता के कारण आपूर्ति व्यवधान जोखिम को कम किया जा सके। मार्च 2025 तक, इस योजना के अंतर्गत छह वर्ष की उत्पादन अवधि में निवेश के लिए अनुमोदित परियोजनाओं के अंतर्गत ₹3,938.5 करोड़ का प्रतिबद्ध निवेश योजना के तीसरे वर्ष तक किए गए ₹4,570 करोड़ के संचयी निवेश से काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त, 25 एपीआई/केसएम/डीआई के लिए उत्पाद क्षमता का विनिर्माण किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2024-25 तक की अवधि में 1,817 करोड़ रुपये की संचयी बिक्री दर्ज की गई है, जिसमें 455 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है, जिससे 1,362 करोड़ रुपये के आयात की बचत की गई है।

(ii) *औषध हेतु पीएलआई योजना:* यह पीएलआई योजना, जिसकी उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन अवधि वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू हुई और जिसका कुल बजटीय परिव्यय ₹15,000 करोड़ है, का उद्देश्य इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर और औषधीय क्षेत्र में अधिक मूल्य वाली वस्तुओं के लिए उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं का संवर्धन करना है और बल्क औषधियों हेतु पीएलआई योजना के अंतर्गत अधिसूचित एपीआई/डीआई/केएसएम के अतिरिक्त अन्य के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। इसने योग्य उत्पादों में निवेश और उत्पादन में वृद्धि की है। मार्च 2025 तक, इस योजना के अंतर्गत एपीआई और डीआई की ₹22,658 करोड़ रुपये की कुल घरेलू बिक्री की गई है। इसमें 1582 करोड़ रुपए मूल्य के 190 एपीआई और डीआई उत्पादों की बिक्री शामिल है जिनका पहली बार घरेलू स्तर पर विनिर्माण किया गया था जिससे उक्त मूल्य के आयात से बचा जा सका।

(iii) *बल्क औषधि पार्क संवर्धन योजना:* इस योजना के अंतर्गत, जिसका कुल बजटीय परिव्यय ₹3,000 करोड़ है, तीन बल्क औषधि पार्क स्वीकृत किए गए हैं और आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में उनकी संबंधित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इनकी कुल परियोजना लागत ₹6,300 करोड़ से अधिक है, जिसमें साझा बुनियादी ढाँचा सुविधाओं के विनिर्माण के लिए प्रत्येक को ₹1,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है। यह पार्क रियायती दरों पर भूमि और बिजली, पानी, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, भाप, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, माल-गोदाम जैसी सुविधाएँ प्रदान करेंगे। तीनों राज्यों की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां निश्चित पूंजी निवेश पर पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, राज्य माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट आदि के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन भी दे रही हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना में यह प्रावधान है कि बल्क औषधियों के लिए पीएलआई योजना में प्राथमिकता वाले उत्पादों के विनिर्माण के लिए इकाइयां स्थापित करने हेतु पार्कों में भूमि आबंटन के लिए आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर एपीआई का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, पीएलआई योजनाओं के अंतर्गत, घरेलू उत्पादन ने एपीआई के आयात का स्थान लेना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, देश में बल्क औषधि के विनिर्माण के संवर्धन हेतु बड़े स्तर पर बुनियादी ढाँचे की स्थापना हेतु बल्क औषधि पार्क विकसित किए जा रहे हैं। जैसे-जैसे इस योजना का विस्तार होगा, परियोजनाएँ परिपक्व होंगी और आगामी पार्कों में बल्क औषधि इकाइयाँ विनिर्माण शुरू करेंगी तो इससे आशा है कि देश में बल्क औषधियों की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता और लचीलापन में वृद्धि होगी।

*****